# उद्योग / डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्र पर शराब उद्योग ने सरकार से सीमा शुल्क को कम नहीं करने की मांग की

Moneybhaskar.Com | Feb 10,2020 05:41:24 PM IST

- सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है

- इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोग रोजगार करते हैं

सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की महीने के अंत में भारत यात्रा पर भारतीय मादक पेय उद्योग ने सरकार से शराब और स्प्रिट्स पर सीमा शुल्क कम नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी शराब पर सीमा शुल्क को कम करने का जोर दे रहे हैं, विशेष रूप से हर्बन व्हिस्की और भारतीय शराब निर्माताओं को डर है कि सीमा शुल्क के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के कारण अमेरिकी आयात पर एक "डोमिनोज़ प्रभाव" पड़ेगा क्योंकि यूरोपीय संघ भी सीमा शुल्क को कम करने के लिए जोर देगा।

## बीसीडी में कोई भी तत्काल और बड़ी कमी घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी

सीमा शुल्क को कम करने पर ट्रम्प की यात्र की चचाओं को वाणिज्य मंत्रलय में फिर से जीवंत कर दिया गया है। भारतीय अल्कोहल पेय कंपनियों के परिसंघ (सीआईएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा है कि यदि सरकार अमेरिका की वाइन और स्प्रिट्स पर कोई रियायत देती है, तो यह बाढ़ के द्वार खोल देगी क्योंकि यूरोपीय संघ समान रियायत की ओर बढेगा। जो हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए सीआईएबीसी की ओर से बार-बार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भारतीय मादक पेय उद्योग के शीर्ष निकाय ने हाल में लिखे पत्र में कहा है कि मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कोई भी तत्काल और बड़ी कमी घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी। पत्र में कहा गया है कि विदेशी सरकारें भारतीय बाजारों तक आसान पहुंच की मांग कर रही हैं (लेकिन) गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से भारतीय कंपनियों को अपने देशों के लिए समान रूप से नकारती हैं।

## भारत में बने शराब उत्पादों पर किसी भी परिपक्वता अवधि पर जोर नहीं देना चाहिए

गिरी के अनुसार भारतीय कंपनियां बीसीडी में कमी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। बीसीडी को अगले 10 वर्षों में 150 से 75 के वर्तमान स्तर से नीचे लाया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अन्य देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ को भारतीय उत्पादों पर गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। उन्हें लेबल पर उत्पाद विवरण के अनुसार भारत में निर्मित मादक उत्पादों को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भारत में बने शराब उत्पादों पर किसी भी परिपक्वता अवधि पर जोर नहीं देना चाहिए। वाणिज्य मंत्री को दिए पत्र में सीआईएबीसी ने अन्य सरकारों के साथ बातचीत करते हुए घरेलू उद्योग के हित को ध्यान में रखने की अपील की है। बेसिक सीमा शुल्क को एक स्तर तक कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कमी को चरणद्घ तरीके से किया जाना चाहिए ताकि भारतीय कंपनियों को भारत में विनिर्माण के विनियामक नुकसान की भरपाई करने के लिए खुद की प्रतिस्पर्धा तैयार करने और निर्माण करने का समय मिल सके। इसके अलावा भारतीय उत्पादों को डंपिंग से बचाने के लिए एक वास्तविक आयात मूल्य दर पर लगाना चाहिए।

## प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोग रोजगार करते हैं

गिरी ने कहा कि मादक पेय पदार्थों का भारतीय निर्यात प्रति वर्ष 200 करोड रुपए है। भारत का विदेशों से आयात 5400 करोड़ है। अमेरिका में केवल निर्यात सिर्फ 50 करोड़ रुपए का है जबकि आयात 1900 करोड़ रुपए का है। भारत के खिलाफ व्यापार बहुत संतुलित है। इस क्षेत्र में रियायत या छूट से लोग असंतुलित होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय शराब उद्योग करोड में 2.5 लाख करोड और वार्षिक राजस्व में 1.25 लाख-करोड़ रुपए देता है। इस उद्योग क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। यह उद्योग क्षेत्र करीब 50 लाख किसानों की आजीविका का समर्थन करता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोग रोजगार करते हैं।

## भारत सरकार सस्ते आयात की अनुमति देकर अपने उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है

गिरी ने कहा कि अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता से पहले इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत सरकार सस्ते आयात की अनुमति देकर अपने उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आईएमएफएल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार करने के लिए डंपिंग और पर्याप्त समय के खिलाफ उचित सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने जल्द ही आईएमएफएल उद्योग पर से कई प्रतिबंध दूर होने की संभावना भी व्यक्त की है।